

of 75,000 tonnes per annum, was commissioned in July, 1981. The total production of newsprint achieved by the Mills during the period July, 1981 to September, 1982 is 21,116 tonnes.

(c) The Mills have requested for various forms of relief, including increased price for domestic newsprint.

“Committee on Environmental Planning”

1528. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have appointed Committee on Environmental Planning recently; and

(b) if so, the details regarding its composition and function? :

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH) : (a) Yes, Sir. A National Committee on Environmental Planning has been set up in April 1981. It was earlier known as the National Committee on Environmental Planning and Coordination set up in 1972.

(b) The Committee is composed of experts from various disciplines, senior Government officials and informed public men. It functions as an advisory body on environmental policy matters and a major responsibility of the Committee is to prepare State-of-the-Environment reports. A statement indicating the composition of the Committee and its terms of reference is laid on the Table of the House. [Pleaced in library. See No. Lt. 5491/82]

समुद्र से यूरेनियम का निकाला जाना

1529. श्री निहाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन समुद्र से यूरेनियम निकालने में सफल हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नया अनुसंधान करने का निर्णय लिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, महासागर विकास विभागों में तथा उर्जा मंत्रालय में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) चीन द्वारा समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालने के बारे में किए गए काम के ब्यौरे की जानकारी सरकार को नहीं है ।

(ख) चूंकि समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालने पर आने वाली लागत काफी निचले ग्रेड वाले अयस्क से यूरेनियम निकालने पर आने वाली लागत से भी बहुत ज्यादा बैठती है, इसलिए समुद्र के पानी से यूरेनियम निकालना आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अलाभकर समझा जाता है । अतः, भारत में इस तरह की तकनीक विकसित करने का कोई बड़ा प्रयास करने का विचार नहीं है ।

Proposal to change Licence Policy

1530. SHRI AJOY BISWAS : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the criteria for issuing an industrial licence; and

(b) whether Government have any proposal to change the licencing policy ?